DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दिल्ली जागरण

मास्टर प्लान की खामियों ने बढ़ाया इंतजार, चल रहा सुधार

अप्रैल 2023 से पहले नहीं मिल पाएगा 20 साल का प्लान

एमपीडी-2041

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

दिल्ली के 20 वर्ष का मास्टर प्लान-2041 (एमपीडी-2041) मिलने में हो रही देर की प्रमुख वजह इसके ड्राफ्ट में मौजूद वही खामियां हैं, जो पहले भी बरकरार रही हैं। ऐसी खामियां, जिनसे देश की राजधानी की सूरत संवरने के बजाय और बिगड़ गई। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए इसके ड्राफ्ट के विभिन्न प्रविधानों को बदला जा रहा है।

बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपीडी-2041 की अधिसूचना में हो रही देरी पर आपत्ति जताई। यहां तक कहा कि 2041 के मास्टर प्लान को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही उम्मीद भी जताई कि फाइनल मास्टर प्लान 30 अप्रैल, 2023 या उससे पहले जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एडिशिनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी द्वारा एमपीडी-2041 की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए कट-आफ तारीखें देने के बाद कही। भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को

एलजी का तर्क, पिछले मास्टर प्लानों से राजधानी हुई और गंदी, बढी झुग्गी बस्तियों व अनधिकृत कालोनियां की संख्या

बताया कि एमपीडी-2041 दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में डीडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा और इसके ड्राफ्ट में कोई भी संशोधन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक किया जाएगा। इसके बाद 15 जनवरी, 2023 तक इसे अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। अप्रैल 2023 तक यह अस्तित्व में आ जाना चाहिए।

पूर्व उपराज्यपाल बैजल ने दे दी थी मंजूरी : एमपीडी-2041 के मौजूदा ड्राफ्ट को पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। नौ जून, 2021 को इसका ड्राफ्ट जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे गए थे। 75 दिन के अंतराल पर डीडीए को इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर 33 हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले। सभी आपत्तियों एवं सुझावों को डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनसुनवाई के जरिये सुना गया। अक्टूबर-नवंबर 2021 में इसके लिए 14 बैठकें हुईं। सभी बैठकों में विभिन्न लोगों, सिविल सोसायटियों, एनजीओ, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशनों, फेडरेशन, प्रोफेशनल, सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों की आपत्तियों को लेकर इस ड्राफ्ट में बदलाव किए गए।

एलजी के निर्देशन में लगातार चल रहा काम : उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशन में एमपीडी-2041 को अधिक व्यावहारिक बनाने का काम लगातार चल रहा है। राजनिवास सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में कई बैठकें हो चुकी हैं। विशेषज्ञों की सलाह के साथ हर खामी को दुरुस्त किया जा रहा है और ड्राफ्ट में ऐसे प्रविधान शामिल किए जा रहे हैं, जिनसे दिल्ली का स्वरूप बेहतर हो सके।

1962 में बना था पहला मास्टर प्लान: राजधानी का पहला मास्टर प्लान 1962 में बना था। इसके बाद वर्ष 2001 और 2021 के मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान अगले 20 वर्ष को ध्यान में रखकर दिल्ली के विकास का खाका होता है।

उपराज्यपाल सक्सेना ने पकड़ीं खामियां

डीडीए सूत्रों का कहना है कि एमपीडी-2041 के फाइनल होने में हो रही देरी की वजह उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसके ड्राफ्ट में किए गए कुछ प्रविधानों में बदलाव करने की संस्तुति रही। उनका मानना है कि बीते कुछ दशकों में जो नीतियां लागू की गई हैं, उनसे दिल्ली में गंदगी के साथ झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों की संख्या में भी वृद्धि होती रही। इसीलिए इस बार ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे शहर को साफ-सुथरा रहे।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
शनिवार
24 सितंबर 2022

फूल वालों की सैर मेला नौ से 15 अक्तूबर तक चलेगा

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक फूलवालों की सैर मेला इस साल नौ अक्तूबर से शुरू होगा। मेले की आयोजन समिति अंजुमन सैर ए गुलफरोशां की महासचिव श्रीमती ऊषा कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि 10 अक्तूबर को फूलों का पंखा दिल्ली के उप राज्यपाल को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पंखा पेश किया जाएगा।

ऊषा कुमारी ने कहा कि 11 अक्तूबर को इंडिया गेट पर सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी। 12 अक्तूबर को महरौली के डीडीए आम बाग में खेलों का आयोजन किया जाएगा। 13 अक्तूबर की शाम को सूफी संत ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर दोनों समुदाय के लोग फूलों की चादर चढ़ाएंगे। इस मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। 14 अक्तूबर को दोनों समुदाय के लोग मिलकर महरौली के योगमाया मंदिर में फूलों का पंखा और चादर चढ़ाएंगे।

यात्रा के संयोजक संजय जैन के बताया कि मेले का समापन 15 अक्तूबर को महरौली के जहाज महल के प्रांगण में होगा।

पार्क में रामलीला के लिए अनुमति मिली

नई दिल्ली, प्र.सं.। उच्च न्यायालय ने दो रामलीला समिति को डीडीए के कीर्ति नगर और त्रिनगर स्थित पार्कों में रामलीला मंचन और दशहरा समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने दोनों समितियों की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।

न्यायालय में याचिका दाखिल कर समितियों ने डीडीए को पार्क में दशहरा और रामलीला मंचन की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने केशव रामलीला समिति को 24 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक त्रिनगर के महर्षि दयानंद पार्क में रामलीला और दशहरा उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी।

विरोध के बीच डीडीए ने खाली कराई चिराग दिल्ली की पार्किंग

जासं, दक्षिणी दिल्ली: डीडीए ने शुक्रवार को चिराग दिल्ली गांव की चिलचिल चौक पार्किंग को खाली करवा लिया। डीडीए की टीम जब पार्किंग को खाली करवाने के लिए गांव पहुंची, तो गांव के सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और पार्किंग खाली कराने का विरोध करने लगे। डीडीए के विरोध में तमाम आप कार्यकर्ता जुट गए। स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए इससे पहले भी गांव की एक पार्किंग को खाली करवा चुका है। उसके बाद गांव वालों को काफी परेशानी हुई। अब यह पार्किंग भी खाली करवा दिए जाने से गांव के लोग अपने वाहन कहां खड़े करेंगे। आम आदमी पार्टी के चिराग दिल्ली वार्ड सचिव सुरेंद्र सहरावत ने बताया कि यह पार्किंग खाली करा दिए जाने से स्थानीय लोगों की समस्या काफी बढ़ गई है।उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिर अब गांव के लोग अपने वाहन कहां पार्क करेंगे। उन्होंने कहा कि डीडीए को गांव के लोगों की पार्किंग की समस्या का समाधान भी करना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times | NEW DELHI SATURDAY SEPTEMBER 24, 2022 ----DATED----

Anti-smog guns, landfill squads in MCD's winter pollution plan

Paras Singh
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Friday announced a series of measures it plans to undertake in order to check air pollution sources during the upcoming winter months.

According to the winter action plan, the civic body has deployed 11 anti-smog guns at different locations prone to dust pollution, including the city's three landfill sites, while teams headed by deputy commissioners have been tasked for surveillance at the 13 pollution hotspots.

Air pollution hit critical levels in Delhi every year during winters as winds die down and temperatures dip. To add to this, farmers in the states of Punjab and Haryana burn harvest residue, sending plumes of smoke that drift over to much of north India, blanketing the region in hazardous pollutants.

Of the 11 anti-smog guns procured by the corporation, two will be deployed at Bhalswa landfill, one each at Okhla and Ghazipur landfills, one unit each at construction and demolition plants located in Rani Khera, Burari, Bakkarwala, Shastri Park and Jahangirpuri, while two units will be deployed atop the Civic Centre, MCD headquarters.

To be sure, scientists have questioned the efficacy of these devices in controlling pollution.

A senior MCD official coordinating the anti-pollution measures said that directions have been issued to the building department to ensure registration of all projects being undertaken over an area of 500 sq-m

The registration of these building projects will help MCD and Delhi Pollution Control Committee (DPCC) teams to ensure dust control measures are being followed by contractors. To ensure compliance, such registrations have been mandated at the time of building plan approval process," the official explained.

MCD has identified 13 pollution hot spots under its jurisdiction – Narela, Bawana, Mundka, Wazirpur, Rohini, RK Puram, Okhla, Jahangirpuri, Anand Vihar, Vivek Vihar, Punjabi Bagh, Mayapuri and Dwarka.

"MCDs zonal deputy commissioners have been designated as the nodal officers for pollution hotspots located in their zones. They will be conducting operation in coordination with other stakeholders like DDA, PWD and Delhi Police," the official said.

Dust remains one of the key pollution components. A study by Indian Institute of Technology, Kanpur has shown that dust from roads, digging and agriculture account for the highest suspended particulate matter sources in Delhi, contributing 38% of PM2.5 and 56% of PM10 in Delhi.

It is estimated that more than 131 tonne of dust is generated every day in Delhi, with construction sites, loose soil, road dust and poorly maintained roads being some of the key contributing factors.

"We have designated sites as local dumping sites across 12 zones. Debris in small quantity can be dumped by general public at these sites from where it will be transported to construction and demolition (C&D) waste processing plants by corporation. However, bulk generators from large construction projects have been directed to dump malba directly at C&D waste processing facilities in Bakkarwala, Ranikhera and Shastri Park," the official quoted above said.

Some progress in terms of procuring machinery to tackle road dust has been made over the last four years, officials said.

"We have deployed 52 mechanical road sweeping machines with target of sweeping 1,560 km per day on average. In addition, 252 water sprinklers will be used for dust control to cover an average length of 1,600 km per day. These water sprinklers will operate twice a day in the 13 identified pollution hotspots," the MCD action plan stated.

Action plan this winter

MCD has announced measures to check air pollution sources

- 11 anti-smog guns deployed at different locations prone to dust pollution
- Teams headed by deputy commissioners tasked for surveillance at 13 pollution hotspots
- All projects undertaken over an area of 500 sq m to be registered to ensure dompliance of dust control measures

Pollution hotspots

Narela, Bawana, Mundka, Wazirpur, Rohini, RK Puram, Okhla, Jahangirpuri, Anand Vihar, Vivek Vihar, Punjabi Bagh, Mayapuri and Dwarka

How dust contributes

A study by IIT-Kanpur has shown dust from roads, digging and agriculture account for 38% PM2.5 and 56% PM10 in Delhi. It is estimated 131 tonnes of dust is generated every day in Delhi

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 24 सितंबर 2022

द्वारका को इस साल के आखिर तक मिल जाएंगे दो एफओबी

मधु विहार बस टर्मिनल और एनएसयूटी के सामने चल रहा है काम

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

द्वारका के लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग अब पूरी होने वाली है। डीडीए ने जिन चार फुट ओवरब्रिज का शिलान्यास 2019 में किया था उनमें से दो का काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं अगले साल दो अन्य एफओबी का भी काम शुरू हो जाएगा।

दिल्ली की पहली प्लांड सब सिटी द्वारका में सड़क पार करने के लिए कोई एफओबी नहीं बनाया गया है। इसके चलते यहां आए दिन हादसे भी होते हैं। 2019 में डीडीए ने यहां चार एफओबी का शिलान्यास किया था। अब इनमें से दो का काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। इनमें से एक एफओबी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएसयूटी) और दूसरा मधु विहार बस स्टैंड के पास बन रहा है। दोनों एफओबी का अगस्त तक काम पूरा करने का टारगेट था। लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। अब इसे इस साल के आखिर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा रोड नंबर 201 और 224 पर भी प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज का निर्माण अगले साल में शुरू करने की तैयारी है।

डीडीए ने किया था 4 एफओबी का शिलान्यास, 2 अन्य अगले साल मिलेंगे

मिलेगी राहत

- प्रस्तावित चार एफओबी में से दो का काम दिसंबर तक होगा पूरा
- रोड नंबर 201 और 224 पर एफओबी का काम अगले साल से हो जाएगा शुरू

डीडीए अधिकारियों के अनुसार रोड नंबर 201 पर फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए पेड़ हटाने की मंजूरी से जुड़ी प्रक्रिया चल रही है। साल 2019 में इन एफओबी के निर्माण का प्रोजक्ट बनाया गया था। लोगों का कहना है कि मधु विहार इलाके में एक भी पार्क नहीं है। ऐसे में लोग सड़क पार कर द्वारका की तरफ जाते हैं। वहीं द्वारका के लोग खरीदारी के लिए मधु विहार आते हैं।

वहीं एनएसयूटी में आने वाले स्टूडेंट्स को भी सड़क पार करने में परेशानी होती है। रोड नंबर-224 पर एक तरफ इंदिरा गांधी अस्पताल है तो दूसरी तरफ द्वारका कोर्ट। लेकिन यहां सड़क पार करने के लिए ज़ेबा क्रॉसिंग तक नहीं है। आम चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इनका शिलान्यास किया था। मधु विहार आरडब्ल्यूए के महासचिव जगदीश नैलवाल ने बताया कि बीते दस साल से यहां एफओबी बनाने की मांग है। अब उम्मीद है कि यह जल्द पूरा हो जाएगा।

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022

Push begins for 5G in Delhi, L-G to chair meeting next week

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, SEPTEMBER 23

DELHIITES COULD soon enjoy high-speed 5G network connectivity as work has begun to assess how infrastructure can be upgraded – from departments and buildings where smaller 'cells' sites can be put up to street furniture where smaller 'cells' can be installed to bolster the network.

Small cell sites are basically meant to enhance the network in areas with high density of mobile phones, such as the crowded Chandni Chowk market or a stadium that accommodates thousands or a Metro station like Rajiv Chowk.

Major agencies and departments such as the Delhi Police, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) and other departments which currently use 4G network will completely shift to 5G network once the project is rolled out.

Delhi L-G V K Saxena will chair a meeting on Tuesday on this front, expected to be attended by officials from the department of telecommunication, Delhi Police, Delhi Metro Rail Corporation, Delhi Development Authority and representatives of telecom firms, sources said.

Two weeks ago, the Delhi Chief Secretary had met prominent telecom firms to discuss the rollout, it is learnt.

"The project is at an initial stage but preliminary work has begun. While telecom firms will roll out 5G, government departments will provide infrastructural support and facilitate the implementation," said a source.

On the installation of the small cells, another source said, "These need to be installed every 200 metres so that consumers – from densely populated areas to upscale colonies – get high-speed network."

Sources said the L-G is set to give his nod for installing these in buildings of the Delhi Police, DMRC, NDMC and DDA. *Archive*

Sources said the L-G is set to give his nod for installing these in buildings of the Delhi Police, DMRC, NDMC and DDA, which come under him.

The Delhi government is expected to give permission for installation in departments and stretches that come under its jurisdiction.

Infrastructural support will be provided through government departments such as the Public Works Department, which looks after major roads. The PWD has already started a survey and some data has been submitted to Geospatial Delhi Limited (GSDL).

As part of its survey, PWD will identify electric poles, hoardings, overhead sign boards, traffic signals, Metro pillars, government offices and school buildings where the project can be taken forward.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, रविवार, 25 सितंबर 2022
NAME OF NEWSPAPERS---------- ----DATED----------

बसों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू, अक्तूबर के पहले सप्ताह तक सड़कों पर उतारी जाएंगी

डीटीसी के बेड़े में जुड़ेंगी 50 नई ई-बसें

बदलती दिल्ली

17 डिपो में दिसंबर तक चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएगा

55 डिपो पर अगले साल तक चार्जिंग स्टेशन बन जाएंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता । दिल्ली परिवहन विभाग (डीटीसी) के बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि नई बसों की आपूर्ति शुरू हो गई है और पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अक्तूबर के पहले सप्ताह तक इन्हें सड़कों पर उतार दिया जाएगा। अभी तक डीटीसी के पास 250 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अब 50 नई बसें आने के बाद कुल बसों की संख्या 300 हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में मौजूदा 7300 बसों की संख्या का बढ़ाकर 11 हजार ले जाने का है, जिसमें 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

नई बसों को तेजी से बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। 17 बस डिपो में दिसंबर तक चार्जिंग स्टेशन तैयार हो जाएंगे। बाकी 55 बस डिपो पर अगले साल तक चार्जिंग स्टेशन तैयार होंगे।

नरेला में पुलिस थाने के लिए जमीन का आवंटन

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के बाहरी इलाके में बसाई जा रही नरेला सब सिटी के विकास की दिशा में डीडीए ने काम शुरू कर दिया है।

हाल ही में डीडीए ने नरेला सब सिटी समेत आस-पास के इलाकों में 11 पुलिस स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की ओर से यहां जल्द ही बसों के आठ नए रूट शुरू किए जाने हैं। इनमें से दो रूट शुरु भी हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों उपराज्यपाल के निर्देश पर डीटीसी ने शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए नरेला पॉकेट-जी और नरेला सेक्टर-ए1 को केंद्रीय सचिवालय से जोड़ने वाले रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है।

छह महीने में पचास नए सीएनजी पंप खुलेंगे

- सात पंप दिल्ली और उससे सटी सीमा पर खोले जाएंगे
- पेट्रोल पंपों पर अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बनेंगे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मार्च 2023 तक करीब 50 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे, जिनमें सात स्टेशन दिल्ली और उससे सटी सीमा पर खुलेंगे। इसको लेकर पेट्रोलियम कंपनियों ने भी आश्वस्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक, करीब 25 सीएनजी स्टेशन खोलने की दिशा में काम चल रहा है। इनमें से कुछ स्टेशन एक से दो महीने के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। बाकी स्टेशनों को भी चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की योजना है। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

मार्च में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए सीधे और छोटे मार्गों का निर्धारण किया गया है। मार्गों को निर्धारित करते वक्त रखे गए लक्ष्यों पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के तहत लक्ष्य रखा गया था कि एनसीआर में पेट्रोलियम कंपनियों के तेजी से सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ानी होगी।

सभी राज्य सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ाएंगे। बीते दिनों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अभी सीएनजी स्टेशन की संख्या सीमित है। इसलिए कुछ तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SEPTEMBER 25, 2022

'1k homes demolished in city, 5.8k people hit'

Action Against 36.5k Houses Across India, 2L Evicted: Report

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: A new report by Housing and Land Rights Network (HLRN) says that the government authorities, at both the central and state levels, demolished over 36,480 homes in 2021, thereby evicting over 2 lakh people from their homes across the country. In Delhi, various land-owning agencies demolished 1,123 homes for various reasons, affecting a total of 5,838 people.

The national capital witnessed several incidents of such demolitions between February and July this year. The report alleged that in most of these cases, due processes were not followed and the affected persons were not rehabilitated. It said "forced evictions" lead to displacement of families, loss of homes and livelihood, disruption of children's education, severe impact on health, and physical and psychological trauma among other consequences.

Among the reasons that led to eviction of people in the national capital are slum-clearance, anti-encroachment or beautification drives and infrastructure projects.

Delhi Development Authority (DDA) carried out several demolition drives to vacate government land in 2021. "In February 2021, DDA demolished 150 houses in Shastri Park. In Dhobi Ghat area, DDA along with police demolished 26 houses. In December 2021, DDA demolished over 140 houses in Kalkaji without any rehabilitation provided to the affected families," HLRN claimed in the report. DDA did not respond to queries sent by **TOI**.

The report highlighted inadequate and delayed resettlement as evicted families have been waiting for rehabilitation for several years. "In many of these cases, the rehabilitation has been ordered by the Delhi high court and the families have paid for alternative housing, often by taking personal loans at high interest rates. In Kidwai Nagar, around 400 affected people have been waiting for the allotment of alternative flats since 2017," said the report.

The report alleged that with the continued lack of coordination between governments and overlapping implementation of schemes for the poor, the evicted families in Delhi are forced to languish in inadequate living conditions, waiting to be rehabilitated by the state.

HLRN in the report recommended to the Centre and state governments that due processes should be followed by ensuring that the free, prior, and informed consent of all affected persons is taken before any eviction project is finalised. The report said alternative accommodation should be urgently provided to all evicted families.

NOWHERE TO GO?

- Over **36,480 homes** were demolished and around **2.1 lakh** people evicted from their homes across urban and rural India in 2021
- In Delhi, 1,123 homes were demolished, affecting 5,838 people in 2021
- Over **25,800 homes** and more than **124,450 people** were evicted across the country from January to July 2022
- Delhi witnessed many such incidents in this year
- The evictions occurred despite the third wave of the Covid pandemic during January-March 2022, and the continued impact on the livelihood and lives of people

Photo for representation

FORCED EVICTION IN INDIA

- At least 100 houses destroyed daily
- At least 567 people lost their homes every day
- At least 24 people evicted every hour

What is forced eviction

'Forced eviction' has been defined by General Comment 7 (1997) of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: The permanent or temporary removal against the will of individuals, families or communities from their homes or land, which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 25 सितंबर 2022

RS---DATED--------------------

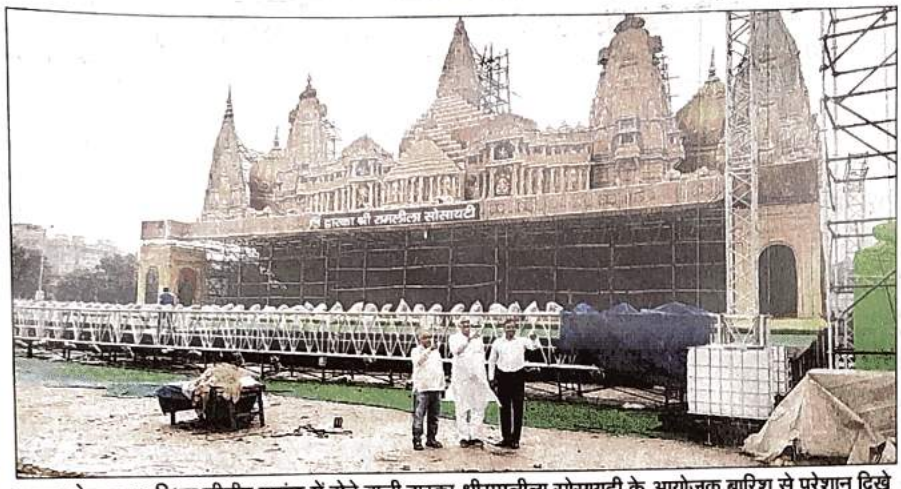

द्वारका सेक्टर-10 स्थित डीडीए ग्राउंड में होने वाली द्वारका श्रीरामलीला सोसायटी के आयोजक बारिश से परेशान दिखे

द्वारका में लीला मैदानों में भरा पानी, कुर्सी-कारपेट भी भीगे

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली में तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से रामलीला मंचन की तैयारियों में बाधा आई है। कुछ आयोजन समितियों के अनुसार, यदि रविवार को भी इसी तरह बारिश होती रही तो सोमवार को मंचन शुरू करने में मुश्किलें आएंगी। द्वारका सेक्टर-10 स्थित डीडीए ग्राउंड में द्वारका श्रीरामलीला सोसायटी के संयोजक राजेश गहलोत ने बताया कि मंच बनकर तैयार है। पांचों प्रवेश द्वार भी बन गए हैं, लेकिन बारिश से कुर्सी व कारपेट खराब हो गए हैं। सोमवार को बारिश थम गई तो रामलीलाओं का मंचन शुरू हो सकता है। कीचड़ की समस्या न हो, इसके लिए रोड़ियों की व्यवस्था की गई है।

मंचन समय पर शुरू करवाने के प्रयास जारी, मगर बारिश नहीं रुकी तो आएगी दिक्कत

द्वारका सेक्टर-13 स्थित डीडीए ग्राउंड में बाल उत्सव रामलीला समिति की ओर से होने वाले रामलीला मंचन के महासचिव हरीश कोचर के अनुसार, बारिश ने कारण तैयारियां काफी प्रभावित हो गई हैं। बारिश को देखते हुए रविवार को होने वाली डांडिया नाइट अब सोमवार को होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि सोमवार से आयोजन शुरू हो। दशरथपुरी में रामलीला एवं दशहरा महोत्सव की संयोजिका पूनम जिंदल ने बताया कि लगातार बारिश से ग्राउंड में भारी भर गया है।

बारिश में भीग गए दहन वाले रावण

रावण का पुतला बनाने वाले कारोबारियों ने बताया कि तीन दिन से लगातार बारिश के कारण उनका काफी नुकसान हो गया है। रावण के पुतले के ढांचे पर लगाया गया कागज गीला होकर उतर गया है। बारिश थमने के बाद अब कारीगरों को दिन-रात काम कर ऑर्डर समय पर पूरा करना होगा। दोबारा से कागज लगाने की कवायद करनी होगी। कागज पिछले सालों की तुलना में पहले ही महंगे हैं। इसलिए काफी नुकसान हुआ है। बांस भी गीले हो गए हैं। यदि आगे धूप नहीं निकलती तो गीले बांस के रावण के पुतले को जलाने में परेशानी आएगी। कारोबारियों ने बताया कि हमारे पास ढांचों को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सभी फुटपाथ पर रखे हैं जो बारिश में भीग रहे हैं।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2022 | 5

ईडब्ल्यूएस रोगियों के मुफ्त इलाज मामले पर डीडीए से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्लीः राजीव गांधी कैंसर संस्थान के ईडब्ल्यूएस रोगियों को निशुल्क इलाज न करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए से जवाब मांगा है। डीडीए को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने को लेकर अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। पीठ ने दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।

एक नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने डीडीए को यह भी बताने को कहा कि अस्पताल आइपीडी में दस प्रतिशत और ओपीडी में 25 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस रोगियों को मुफ्त इलाज दे रहा है या नहीं? अगर, ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दाखिल याचिका में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अस्पताल ने दो दशक तक ईडब्ल्यूएस रोगियों का मुफ्त इलाज करने की शर्त पर डीडीए से सस्ती दर पर जमीन ली है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

TIMES CITY

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022

Damselflies In Distress? Why Stark Change In Rain Patterns May Hurt

Unfavourable Conditions Can Reduce Chances Of Successful Reproduction

Priyangi.Agarwal
@timesgroup.com

New Delhi: A week-long survey conducted to determine the diversity and density of dragonflies and damselflies has found seven to 25 species at the seven biodiversity parks of the Delhi Development Authority (DDA). They are important to the environment as predators (particularly of mosquitos) and prey to birds and fish.

As these insects require stable oxygen levels and clean water, scientists consider them reliable bioindicators of the health of an ecosystem. However, scientists said scanty rain in the first 20 days of September, followed by an intense rain activity in the past four days, affected the density of dragonflies and damselflies.

All seven biodiversity parks were covered this time, but before this, the survey was conducted in 2018 where 25, 9 and 5 species were recorded in Yamuna Biodiversity Park, Neela Hauz Biodiversity Park and Tilpath Valley Biodiversity Park, respectively.

With indications of changes in rainfall patterns over the recent years, the untimely emergence of adult dragonflies and damselflies is likely to expose them to less favourable conditions. "Delhi saw an intense rain activity in the past few days, but the monsoon season is likely to withdraw soon. As dragonflies and damselflies have only a few weeks to live and reproduce, the unfavourable conditions they face can reduce their chances of successful reproduction and also cause direct mortality. Rain distribution range shifts can have other negative impacts on species apart from shrinking of suitable habitats," said Faiyaz Khudsar, scientist incharge, biodiversity parks programme.

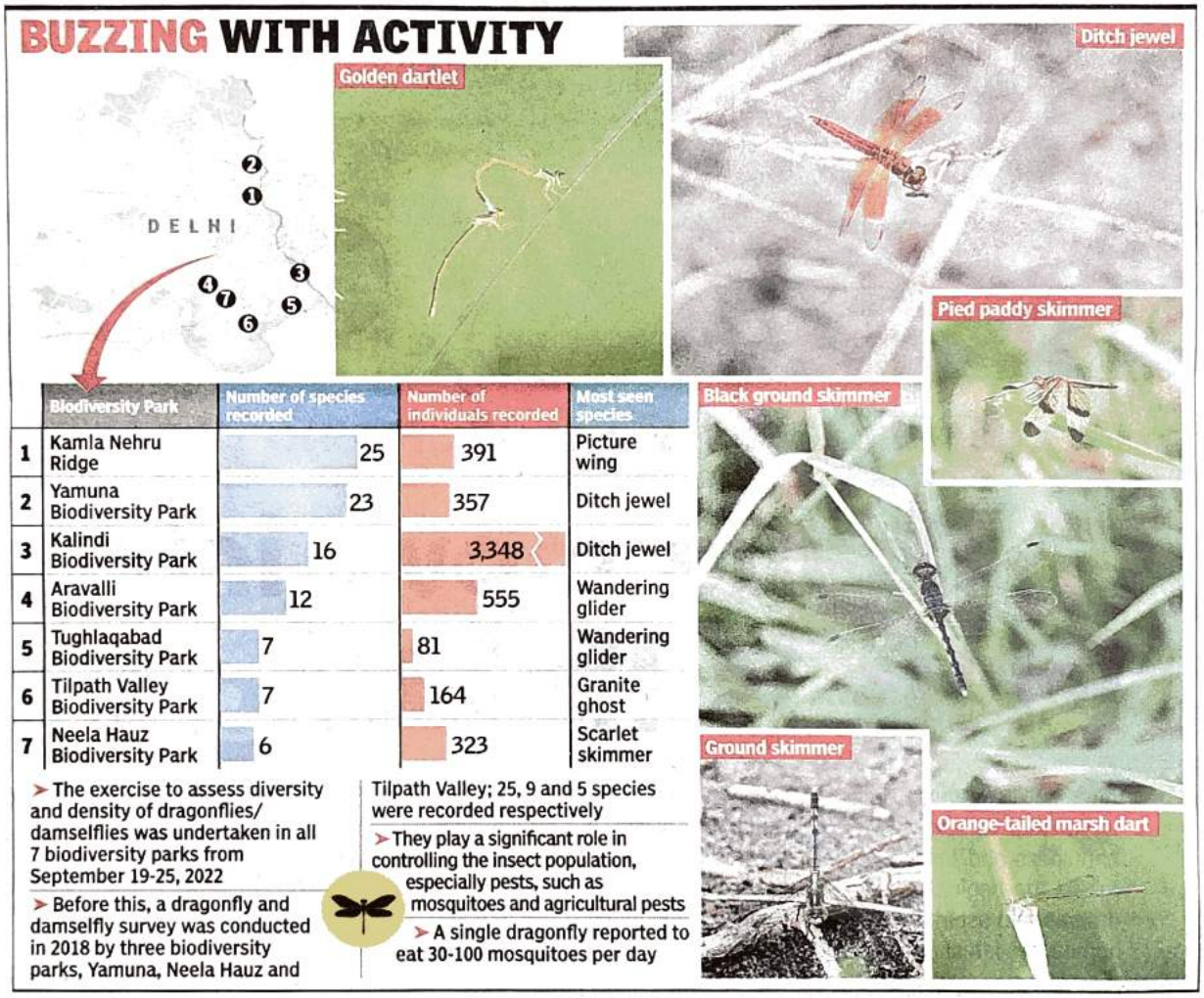

According to scientists, higher water temperatures cause the larvae to develop more quickly and emerge as adults sooner, thus affecting their availability throughout the monsoon due to their short life span. It has also been observed that the individuals that develop in warmer water tend to develop smaller wings compared with the body size.

As the relative wing size decreases, they will experience a higher wing load, making these individuals with less dispersal ability. It affects their ability to move around and predate harmful pests, including mosquitos.

"Water pollution has a negative impact on dragonflies due to their reliance on aquatic ecosystems throughout their life, making them important environmental indicators of water quality. They are biological controllers of mosquitoes and, therefore, cut health expenditure burden by reducing the impact of vector-borne diseases like malaria, dengue and chikungunya. A single dragonfly is reported to eat 30-100 mosquitoes per day," said Khudsar.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

NEW DELHI
MONDAY
SEPTEMBER 26, 2022

Hindustan Times

Erratic rain, severe heat may have hit Delhi's dragonfly count: Survey

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: A dragonfly survey carried out across the seven biodiversity parks in Delhi over the past week suggests significant behavioural changes in the insect's life cycle, likely due to the climate crisis and erratic rainfall patterns this year, scientists said on Sunday, adding these alterations need to be observed over the next few years.

The survey, conducted by scientists and technical staff of the Delhi Development Authority's (DDA) biodiversity parks with students from Hansraj College, Amity University, Jamia Millia Islamia and others between September 19 and 25, found that there are 25 different species of dragonflies and damselflies in Delhi alone and over 51 species across the National Capital Region. The survey counted 5,219 individual dragonflies and damselflies across the seven biodiversity parks in Delhi.

Delhi's first-ever dragonfly count was held across NCR in 2018, with the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, Okhla Bird Sanctuary, Dhanauri wetland, Surajpur wetland, Najafgarh Jheel, Basai wetland, Lodhi Garden and Sanjay Van surveyed. The biodiversity parks covered then included the Yamuna Biodiversity Park, Aravalli Biodiversity Park and the Neela Hauz Biodiversity Park. The 2018 count, carried out by the Bombay Natural History Society and World Wildlife Fund, led to the discovery of 25 dragonfly species.

'25 species found in Delhi'

Biodiversity park	Species spotted	Individuals spotted	Common species
Yamuna Biodiversity Park	23	357	Ditch Jewel
Aravalli Biodiversity Park	12	555	Wandering Glider
Kamla Nehru Ridge	25	391	Picture Wing
Tughlaqabad Biodiversity Park	7	81	Wandering Glider
Neela Hauz Biodiversity Park	6	323	Scarlet Skimmer
Tilpath Valley Biodiversity Park	7	164	Granite Ghost
Kalindi Biodiversity Park	16	3,348	Ditch Jewel

A black ground skimmer.
BIODIVERSITY PARKS PROGRAMME

Scientists, however, said that the number of dragonflies this year cannot be compared to 2018, as the previous survey was conducted only at three biodiversity parks, but the significant behavioural changes in the insect's life cycle do need to be observed over the next few years. "There was good rainfall when the monsoon first hit the region, after which there was a long hot and dry spell, leading to the Yamuna river nearly drying up, and then it rained again over the last few days. This has confused the dragonflies as they lay eggs when it rains. So, they laid eggs in the beginning of monsoon and then entered the nymph stage that normally remains underwater for a long time. Because the wetlands dried up, the nymphs grew up quicker and had a shorter lifespan. When it rained again, the dragonflies laid eggs again—which is unusual. It is now a matter of research for the next year to see what will happen to the eggs and how this shift will impact their population. One year's data is not enough to make a definitive comment," Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of the Biodiversity Parks Programme, said. He added that the nymph stage is the most important regulatory function of the dragonfly as it feeds on mosquito larvae and reduces its population, thereby reducing the possibility of several vector-borne diseases spreading across the region.

Experts believe that a healthy population of dragonflies determines the quality of any ecosystem. The network of seven DDA Biodiversity Parks in Delhi represents both the important ecological landforms—the Yamuna river and Aravalli hill range—in the region. To be sure, any study of these biodiversity parks and its findings represent the true picture of the quality of ecosystems here.

"Effort has been made to assess the population of dragonflies and damselflies in all the biodiversity parks to ascertain the quality of ecosystems, which ultimately provides environmental sustainability and resilience to a city like Delhi. The count of dragonflies and damselflies indicates the quality of water and health of the wetland ecosystem," Khudsar said.

This year, the 457-acre Yamuna Biodiversity Park reported 23 species of the insect—a drop from 2018, when 25 species were recorded—including 357 individuals. The ditch jewel was the most commonly spotted species here and was also the most spotted species at the 400-acre Kalindi Biodiversity Park, which recorded 16 species and 3,348 individuals. Both of these biodiversity parks represent floodplain ecosystems. While Yamuna Biodiversity Park had the highest number of species, Kalindi had the highest individual count of dragonflies and damselflies. Khudsar, meanwhile, added that a significant change from 2018 was the lack of common picture wing dragonflies in Yamuna Biodiversity Park—a species that was the most common here in 2018.

The 692-acre Aravalli Biodiversity Park recorded 12 species and 555 individuals. The 175-acre Tilpath Valley recorded seven species—an increase from five species in 2018—and 164 individuals. The 320-acre Tughlaqabad Biodiversity Park had seven species and 81 individuals. The 215-acre Kamla Nehru Ridge had 25 species and 291 individuals and the 10-acre Neela Hauz had six species—a drop from nine species in 2018—and 323 individuals. These five biodiversity parks represent the last spur of Aravalli range. While the lowest count of dragonflies was observed in Tughlaqabad, the least number of species was in Neela Hauz, given its small size.

The wandering glider was the most commonly spotted species in the Aravalli and Tughlaqabad, common picture wing in Kamla Nehru, scarlet skimmer in Neela Hauz and granite ghost in Tilpath Valley Biodiversity Park. "This is a good time to survey dragonflies as monsoon is when they can be seen in large numbers as they start breeding. So, any survey needs to be conducted around August-September," said Aisha Sultana, ecologist, Biodiversity Parks Programme.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022 DATED

Full Of Life: 'Floating' Solar Panels To Harness The Sun

SANJAY LAKE REVAMP: Project Will Help Generate Power To Meet The Energy Needs Of At least 50 DDA Parks In East Delhi

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Sanjay Lake near Mayur Vihar in east Delhi is going to boast of the national capital's first 'floating' solar power plant if the Delhi Development Authority's (DDA) plans fructify. The plant is expected to generate between 1 and 1.5 megawatt of solar power, which would meet the electricity needs of 50 DDA parks spread across east Delhi.

The authority is carrying out the ecological restoration of Sanjay Lake, one the largest green areas in east Delhi that is spread over 170 acres, including the lake itself, which is spread over 52.3 acres. Sources said that while beautification work, including a recently installed 'selfie-point' and seating areas have come up, the most important element of the entire area is the lake.

Senior DDA officials recently held a meeting with the Delhi Jal Board, which has taken up the work of rejuvenation of Sanjay Lake, including de-silting work. While some parts of the lake are used for boating and recreational purposes, most of the waterbody is not part of any other function. Officials said that there are plans to establish the floating solar power plant on one-third of the area in the middle portion of the lake.

While the power plant is still at a planning stage, it would see solar panels being mounted on floating structures being kept on the lake when a final decision is taken by DDA. Similar floating solar power plants have come up on waterbodies in states like Telangana, Andhra Pradesh, and Kerala.

At these plants, an array of solar modules is mounted on floating platforms, which consist of inverter, transformer and a HT breaker. The floating platform is made of high-density polyethylene material. While DDA's proposed solar power plant would be much smaller in scale, it would be a first for the national capital.

Sanjay Lake has always been a recreational area with the lake and the ducks attracting visitors but DDA has been working on improving the entire area and making it the best recreational hub in east Delhi. In the last few years, DDA has developed facilities like an amphitheatre, walking and cycling tracks, sitting areas, etc.

Sources said that the authority is working on more facilities like nature trails, lake view plazas and courts, food court, observation deck, meditation garden, open gym, play area for children, cactus garden, duck house, jungle themed play area, etc. To encourage art in a public space, DDA has also been developing an 'artist court', sculpture court, and a craft hut in the area.

The authority had planned to plant 5,000 saplings of native species during this monsoon, but it was to be carried out as part of compensatory plantation for an infrastructure and approval was not received in time. The delay means that DDA would now have to wait for the next season to carry out large-scale plantation in the area.

DDA doesn't have enough space available in the capital to provide to different agencies for their compensatory plantation requirement and that is why its plantation drives are aligned to cater to this need.

"It is a protected forest and, therefore, it needs to have a character of a forest. Efforts have been made to improve the area but still a lot needs to be done," said Rajeev Kumar Tiwari, DDA's principal commissioner (horticulture), when asked about plans to rejuvenate the Sanjay Lake greens.

Sources said that the water in the lake gets dirty as unclean water gets mixed with it and that is the reason why there are also plans of a sewage treatment plant (STP) near the lake to ensure that the water entering the lake is clean.

The man-made lake, created in the 1970s, has no water catchment areas and depends on rainwater and other sources for supply of water, an official said. To augment the water in the lake, there are plans to use water from a nearby stormwater drain, for which the STP would be used. The STP would ensure that the lake gets more treated water from the drain.

The authority has also been working on a 'Bioswale' for ground recharge, which would also provide natural beauty, an official said on the condition of anonymity. A bioswale is a ditch or a channel with vegetation, where stormwater runoff is concentrated to remove debris and help in recharging groundwater.

DDA is trying to restore the green space of the area and also provide space to the public to experience the natural beauty without disturbing it, the official said. He added that the Sanjay Lake has a large number of Eucalyptus trees, which were planted way back in the 1970s and 80s and are an impediment in giving the area a forest cover due to their struct structure.

5K SPECIES OF PLANTS, NATURE TRAILS AND MORE

Photos: Rajesh Mehta

170.6 acres
Total area of Sanjay Lake and green space around it

52.3 acres
Area of the waterbody

1-1.5 MW
Generation capacity of 'floating' solar power plant being planned on one-third of the lake's area

Visakhapatnam's floating solar power project on Meghadrigedda reservoir

5,000 Native species | DDA plans to plant in the area

Facilities that have come up near Sanjay Lake

- Selfie point
- Amphitheatre
- Walking trail
- Cycling track
- Green zone
- Mounds
- Nature trails
- Pathways
- Benches and sitting platforms

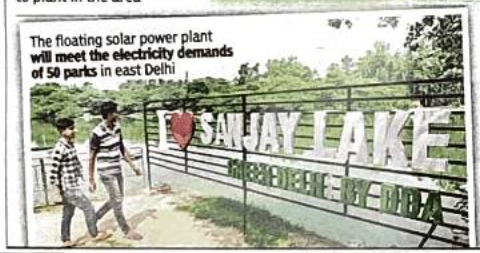

The floating solar power plant **will meet the electricity demands of 50 parks** in east Delhi

Restoration and rejuvenation of Sanjay Lake

- Delhi Jal Board has taken up the work of desilting and rejuvenating the lake
- DDA plans large-scale plantations in the green area surrounding the lake
- DDA intends to give the green area around Sanjay Lake the feel of a forest
- Some parts of the lake are used for activities like boating, etc
- DDA plans to establish a 'floating' solar power plant on the remaining part of the lake
- Solar panels will be mounted on floating structures

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
NAME OF NEWSP **THE INDIAN EXPRESS**, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2022

SURVEY'S FINDINGS

What lower rain in Delhi this year has meant for dragonflies, damselflies

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, SEPTEMBER 25

A SURVEY of dragonflies and damselflies at Delhi's biodiversity parks indicates that low rainfall this year may have impacted their life cycles and numbers.

In a week-long survey that concluded on Sunday, a total of 25 species of dragonflies and damselflies were recorded across seven biodiversity parks.

The Kamla Nehru Ridge recorded the maximum number of species – 25. The Yamuna Biodiversity Park recorded 23 species, a little less than the 25 species recorded in 2018. In terms of the number of individuals recorded, the Kalindi Biodiversity Park recorded the highest number at 3,348, followed by the Aravalli Biodiversity Park where 555 individuals were counted.

The last such survey was conducted in 2018 at the Yamuna, Tilpath Valley and Neela Hauz Biodiversity Parks. The Neela Hauz biodiversity park also recorded a fewer number of species this year – just six – as compared to 2018, when nine species were counted.

Species that were recorded include the Scarlet Skimmer, Picture Wing dragonfly and the Granite Ghost.

In addition to counting the number of species in the two main ecosystems of Delhi – the Aravallis and the Yamuna – the survey was also meant to determine whether the deficit in rainfall in Delhi this monsoon has had any impact on dragonflies and damselflies.

Faiyaz Khudsar, scientist incharge, Biodiversity Parks Programme at the Centre for Environment Management of Degraded Ecosystems, said, "Since the temperature was high and rainfall was low, there was little water in the river and the floodplain wetlands are shrunken. The nymph, which is one of the stages of the life cycle of the dragonfly, stays in the water for a long period of time and is a voracious feeder of mosquito larvae. When the temperature is high and there's less rainfall and less water, the nymph grows quickly into an adult. Since dragonflies have small life spans, they die quickly. That's the scenario this time."

(Clockwise from above) Golden Darlet; Pied Paddy Skimmer; Ditch Jewel. As many as 25 species of dragonflies and damselflies were recorded across seven biodiversity parks. *DDA Biodiversity Parks*

"When the temperature is high and the metamorphosis is faster, the wing size also tends to reduce. And, when the wing size reduces, their dispersal can reduce drastically. Since their movement is reduced, their foraging – they feed on adult mosquitos – is also reduced," Khudsar added.

The city has recorded a deficit in rainfall for the monsoon so far. For the month of September, there was a large deficit in rainfall till this week when monsoonal rainfall picked up again.

With rainfall having picked up towards the end of the week, the scientists noticed that the dragonflies began laying eggs again. "They have started breeding again thinking that it is the monsoon. Soon, winter will come, and what's going to happen to those eggs?" Khudsar said. Collecting data of this sort for a few years can help track the changes taking place in the ecosystem, and it could be too soon now to arrive at concrete conclusions, he added.

Dragonflies serve as biological control for mosquitoes. They are also an indicator of water quality in wetlands and water bodies since polluted water is detrimental to them.

New Delhi

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2022 ERS----------DATED----------

सर्दी में फूलों की खुशबू से महकेंगी सड़कें

निहाल सिंह ● नई दिल्ली

- एलजी ने डीडीए, एमसीडी और लोक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे फूलों वाले पौधे लगाने के दिए निर्देश
- जी-20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखकर पूरी दिल्ली में सुंदरता के लिए जगह-जगह रोपे जाएंगे पौधे

सर्दियों में दिल्ली गैस चेंबर बनेगी या नहीं, यह तो कहना मुश्किल हैं, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली फूलों की खुशबू से महकेगी। जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने फूलों वाले पौधे सड़कों के किनारे रोपने को कहा है। फूलों की प्रजातियों के नाम भी इन एजेंसियों को भेजे गए हैं और उन्हें लगाने वाले स्थानों की सूची के साथ इस पर प्रगति रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई है।

राजधानी में अब तक एनडीएमसी इलाके की 101 एवेन्यू रोड पर ऐसे प्रयोग किए जाते थे। सर्दियों में गुनगुनी धूप के बीच लुटियंस दिल्ली से गुजरने वाले लोग इन फूलों की तरफ आकर्षित होते थे। कई बार लोगों को वाहन रोककर फूलों के साथ सेल्फी लेते हुए भी लोग देखा गया है।

फूलों देखने के लिए लोग राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन भी जाते हैं। शायद इसलिए उपराज्यपाल ने एजेंसियों को सर्दियों में खिलने और महकने वाले फूलों के पौधे लगाने के लिए कहा है। चूंकि राजधानी में प्रमुख सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं, ऐसे में सड़कों के किनारे पौधे रोपने का कार्य यही विभाग करेगा। डीडीए अपनी कालोनियों और अपने पार्कों में फूलों वाले पौधे लगाएगा। दिल्ली नगर निगम ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। एमसीडी भी मुख्य पार्कों से लेकर कालोनी के पार्कों और फ्लाईओवर के नीचे इन पौधों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी करीब 1400 किमी सड़कों का रखरखाव करता है, जबकि एमसीडी के पास 15 हजार से अधिक 5500 एकड़ भूमि वाले पार्क हैं।

शांति पथ पर सड़क किनारे लगाए गए फूलों वाले पौधे ● जागरण आर्काइव

कर्तव्य पथ के लिए विशेष तैयारी कर रहा एनडीएमसी

कर्तव्य पथ के सुंदरीकरण के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास रंग-बिरंगे फूल पौधे लगाए जाएंगे। कर्तव्य पथ के लान में वर्टिकल प्लावर लगाए जाएंगे। इसमें एनडीएमसी की तैयारी बासकेट में फूलों वाले पौधे लगाने के साथ छह से सात फीट ऊंचे दिल और अन्य आकृति में पौधे लगाए जाएंगे।

ये पौधे लगाए जाएंगे

कोसमोस, फ्लोक्स, पोपी, बर्बीना, डहेलिया और अन्य

10 नवंबर तक बीजारोपण

15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इन पौधों का बीजारोपण किया जा सकता है। ऐसे में यह पौधे जनवरी 15 तक अच्छी तरह से फूल देने लायक हो जाते हैं, जो कि अप्रैल के अंतिम माह चलते हैं। ट्यूलिप के पौधे विदेश मंगाए जाते हैं, जिन्हें रोपा जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। शनिवार • 24 सितम्बर • 2022

भूजल मामले में दिल्ली सबसे निचले पायदान पर : गुप्ता

भाजपा ने कई स्थान पर चलाया जल संरक्षण अभियान

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत कई स्थानों पर जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किशनगढ़ गांव के 200 साल पुराने सूखे तालाब को पुनर्जीवित करने के प्रयासों और जल संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ग्राम वासियों और डीडीए को धन्यवाद दिया।

गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के 200 तालाबों को पुनर्जीवित करने के वायदों को याद दिलाते हुए कहा कि केजरीवाल सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए काम करते है। आज तक जिन 200 तालाबों को पुनर्जीवित करने का वायदा किया था, उनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। हर वर्ष अलग-अलग इलाकों में .5 से 2 मीटर तक भू जल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे बुरी हालत दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, शाहदरा और उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। कार्यक्रमों में भाजपा के प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, हर्ष मल्होत्रा एवं दिनेश प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजन तिवारी, कार्यक्रम के संयोजक सुनील यादव, महिला मोर्चा की अध्यक्षा योगिता सिंह शामिल हुए।

पंजाब केसरी DELHI • 24 सितम्बर, 2022 • शनिवार

गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): नरेला सेक्टर-ए 5 डीडीए जनता फ्लैट में रहने वाले लोग इन दिनों गंदे पानी की समस्या से परेशान है, इलाके में लंबे समय से पीने का पानी गंदा आ रहा है जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में कई माह से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लोगों का कहना है कि जब भी पानी आता है तो वह कीचड़ या मिट्टी युक्त होता है। अगर पानी साफ आ भी जाए तो वह बदबूदार होता है। घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। सोमवार • 26 सितम्बर • 2022

रामलीलाओं के लिए सजे मंच

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी सोमवार से राममय होने के लिए तैयार है। अनुमान है दिल्ली शहर में 11 दिनों तक चलने वाली करीब एक हजार से अधिक रामलीलाओं का मंचन होगा। यहां पर मुख्य रामलीलाएं लालकिला, पीतमपुरा, रोहिणी पार्क, कश्मीरी गेट, पूर्वी दिल्ली के कैलाश कोलोनी, डीडीए पार्क सीबीडी ग्राउंड में होगी।

रामलीला मैदान मे अयोजित होने वाली दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला श्री रामलीला कमेटी रामलीला में इस बार अयोध्या के राम मंदिर के प्रारूप के पांच मंजिला मंच पर रामलीला का मंचन होगा। कमेटी के अध्यक्ष अजय अग्रवाल कहा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समय से मंचित हो रही। 200 साल से ज्यादा पुरानी रामलीला मैदान की इस रामलीला से लोगों का भावनात्मक लगाव है, भाईचारे सांकृतिक सौहार्द की प्रतीक है। इस रामलीला की एक और आकर्षण इसकी मनोरम झांकी की जुलूस है, जो अदभुत होती है, इस बार 11 दिनों में 22 झांकी जुलुस निकलेगी। रविवार को लालकिला मैदान में 26 सितम्बर से शुरू हो रही विश्व की सबसे बड़ी और लोकप्रिय लव कुश रामलीला के सभी कलाकारों ने अपने किरदार के फुल कॉस्ट्यूम ने मीडिया और आए मेहमानों के सम्मुख लीला के कुछ दृश्यों की रिहर्सल से समां बांध दिया।